शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 50 वां वर्ष

ई – पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/shailsamachar

वर्ष 50 अंक – 19 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 5 – 12 मई 2025 मूल्य पांच रूपये

नादौन में ई–बस डिपो के लिए खरीदी जमीन आयी सवालों में

> - सरकार की जमीन 2,60000 में खरीद कर सरकार को ही करीब सात करोड़ में बेच दी।
> - खरीदी – बेची गयी जमीन विलेज कॉमन लैण्ड है
> - 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी जमीनों की सुरक्षा के लिये देश के सभी मुख्य सचिवों को कड़े निर्देश दे रखे हैं
> - यह खरीद बेच तहसीलदार से लेकर मुख्य सचिव और मंत्री परिषद सबके संज्ञान में रही है।

शिमला/शैल। सुक्खू सरकार ने बस किराये में 15% की बढ़ौतरी आदेशित की है। इस बढ़ौतरी से पहले न्यूनतम किराया दस रूपये कर दिया गया था। इस बस किराया बढ़ौतरी पर प्रदेश भर में रोष है। स्वभाविक है कि सरकार जब वित्तीय संकट से गुजर रही है तब राजस्व बढ़ाने के लिये सरकारी तंत्र आम आदमी की जेब की ओर ही देखेगा क्योंकि यही उसे सबसे आसान रास्ता नजर आता है। इसलिये सुक्खू सरकार ने प्रदेश के हर वर्ग पर किसी न किसी तरह से बोझ डाला ही है। अस्पताल से लेकर स्कूल तक सब प्रभावित हुये हैं। सुक्खू सरकार अपने खर्चे कम करने के बजाये जब आम आदमी पर बोझ डालेगी तो निश्चित रूप से आम आदमी भी सरकार के हर काम पर पैनी नजर रखना शुरू कर देगा। इसी कड़ी में परिवहन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री के अपने चुनाव क्षेत्र नादौन में प्रस्तावित ई-बस डिपो आजकल विशेष चर्चा का विषय बना हुआ है। इस ई-बस डिपो के लिये परिवहन विभाग ने नादौन में मुख्यमंत्री के अपने गांव के पास करीब सात करोड़ में जमीन खरीदी है। लेकिन इस जमीन पर अभी बस डिपो बनाने के नाम पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है। बल्कि खरीदी गई जमीन पर अभी परिवहन विभाग का बोर्ड तक नहीं लगा है। बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि शायद सरकार को यह जमीन खरीदने की ही जल्दी थी इस पर कुछ करने की नहीं। क्योंकि इस खरीद पर अब जो सवाल उठ रहे हैं वह बहुत ही गंभीर हैं उनसे सरकार की नीयत और नीति दोनों पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं।

यह जमीन नादौन क्षेत्र के चार लोगों राजेंद्र सिंह राणा, प्रभात चन्द, अजय कुमार और रसीला राम से 6,82,04520 रुपए में खरीदी गयी है। इन लोगों ने यह जमीन राजा नादौन महेश्वर चन्द के जी. पीए. हरभजन सिंह के माध्यम से 2015 में 2,60,000 रुपए में खरीदी थी और 2024 में इसी जमीन को एच.आर.टी.सी. को करीब सात करोड़ में बेच दिया गया। यहां पर यह सवाल उठ रहा है कि जब 1974 में लैण्ड सीलिंग एक्ट लागू होने के बाद राजा नादौन के पास बची ही 316 कनाल जमीन थी तो राजा नादौन ने जी.पी.ए. के माध्यम से कैसे हजारों कनाल जमीन बेच दी। राजा नादौन को 1897 में अंग्रेज सरकार के दौरान 1,59000 कनाल जमीन बतौर जागीर मिली थी। यह जमीने रियासत नादौन के 329 गांव में फैली हुई थी। लेकिन इन जमीनों पर स्थानीय लोगों के बर्तनदारी के हक सुरक्षित रखे गये थे। यह जमीने पंजाब विलेज कॉमन लैण्ड एक्ट के तहत शामलात देह और फिर 1974 में हिमाचल प्रदेश विलेज कॉमन लैण्ड एक्ट के तहत यह जमीन सरकार की मलकीलत हो गयी। विलेज कॉमन लैण्ड की खरीद बेच नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इस संद्धर्भ में जनवरी 2011 में एक सख्त फैसला देते हुये पूरे देश के मुख्य सचिवों को ऐसी जमीनों की सुरक्षा के विशेष निर्देश देते हुये समय-समय पर इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को सूचित करने के आदेश हुये हैं। लेकिन राजा नादौन ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दिसम्बर 2011 में जी.पी.ए. बनाकर इन जमीनों को बेचना शुरू कर दिया। कई बड़े अधिकारियों और राजनेताओं ने सैकड़ो बीघे के हिसाब से इन जमीनों की खरीद की है।

अब जब एच.आर.टी.सी. ने इन लोगों से जमीन खरीदी तब यह मामला पूरे प्रशासन के सामने आ चुका है क्योंकि इसका फैसला वाकायदा मंत्रिमंडल की बैठक में

शेष पृष्ठ 8 पर....................

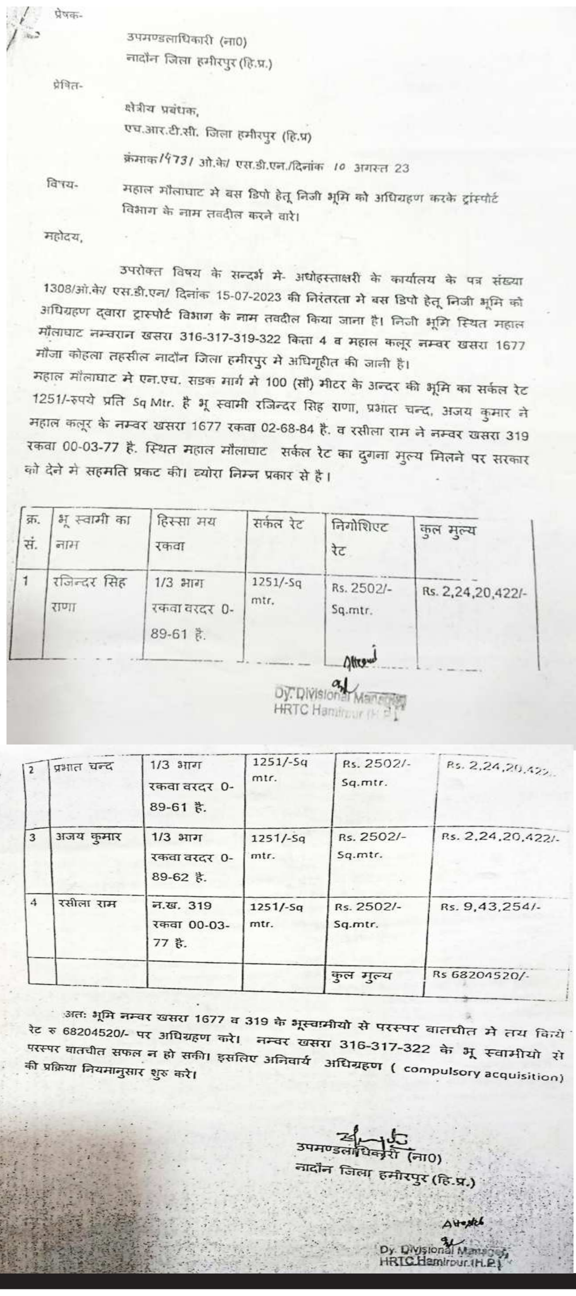

प्रेषक-

उपमण्डलाधिकारी (ना0)
नादौन जिला हमीरपुर (हि.प्र.)

प्रेषित-

क्षेत्रीय प्रबंधक,
एच.आर.टी.सी. जिला हमीरपुर (हि.प्र)

क्रंमाक/473/ ओ.के/ एस.डी.एन./दिनांक 10 अगस्त 23

विषय- महाल मौंलाघाट मे बस डिपो हेतू निजी भूमि को अधिग्रहण करके ट्रांस्पोर्ट विभाग के नाम तवदील करने वारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ मे- अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय के पत्र संख्या 1308/ओ.के/ एस.डी.एन/ दिनांक 15-07-2023 की निरंतरता मे बस डिपो हेतू निजी भूमि को अधिग्रहण द्वारा ट्रास्पोर्ट विभाग के नाम तवदील किया जाना है। निजी भूमि स्थित महाल मौंलाघाट नम्वरान खसरा 316-317-319-322 किता 4 व महाल कलूर नम्वर खसरा 1677 मौजा कोहला तहसील नादौन जिला हमीरपुर मे अधिगृहीत की जानी है।
महाल मौंलाघाट मे एन.एच. सडक मार्ग मे 100 (सौं) मीटर के अन्दर की भूमि का सर्कल रेट 1251/-रुपये प्रति Sq Mtr. है भू स्वामी रजिन्दर सिह राणा, प्रभात चन्द, अजय कुमार ने महाल कलूर के नम्वर खसरा 1677 रकवा 02-68-84 है. व रसीला राम ने नम्वर खसरा 319 रकवा 00-03-77 है. स्थित महाल मौंलाघाट सर्कल रेट का दुगना मुल्य मिलने पर सरकार को देने मे सहमति प्रकट की। ब्योरा निम्न प्रकार से है।

क्र. सं.	भू स्वामी का नाम	हिस्सा मय रकवा	सर्कल रेट	निगोशिएट रेट	कुल मुल्य
1	रजिन्दर सिह राणा	1/3 भाग रकवा वरदर 0-89-61 है.	1251/-Sq mtr.	Rs. 2502/- Sq.mtr.	Rs. 2,24,20,422/-
2	प्रभात चन्द	1/3 भाग रकवा वरदर 0-89-61 है.	1251/-Sq mtr.	Rs. 2502/- Sq.mtr.	Rs. 2,24,20,422/-
3	अजय कुमार	1/3 भाग रकवा वरदर 0-89-62 है.	1251/-Sq mtr.	Rs. 2502/- Sq.mtr.	Rs. 2,24,20,422/-
4	रसीला राम	न.ख. 319 रकवा 00-03-77 है.	1251/-Sq mtr.	Rs. 2502/- Sq.mtr.	Rs. 9,43,254/-
				कुल मुल्य	Rs 68204520/-

अतः भूमि नम्वर खसरा 1677 व 319 के भूस्वामीयो से परस्पर बातचीत मे तय किये रेट रु 68204520/- पर अधिग्रहण करे। नम्वर खसरा 316-317-322 के भू स्वामीयो से परस्पर बातचीत सफल न हो सकी। इसलिए अनिवार्य अधिग्रहण (compulsory acquisition) की प्रक्रिया नियमानुसार शुरु करे।

उपमण्डलाधिकारी (ना0)
नादौन जिला हमीरपुर (हि.प्र.)

Dy. Divisional Manager,
HRTC Hamirpur (H.P.)

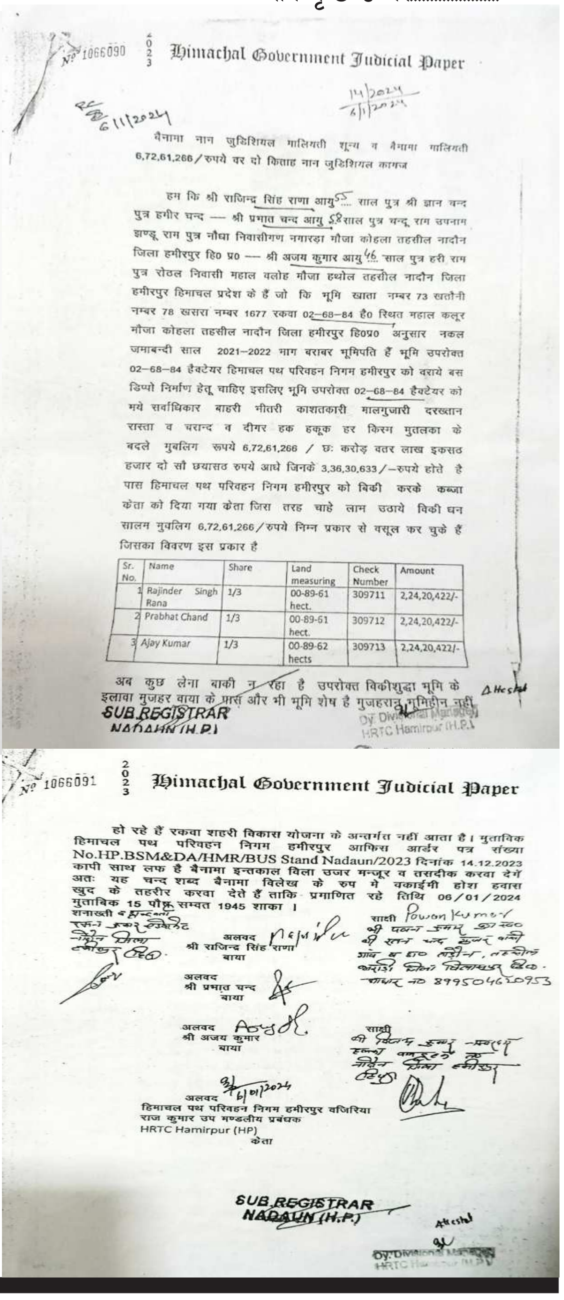

№ 1066090 2023 Himachal Government Judicial Paper

बैनामा नान जुडिशियल मालियती शून्य व बैनामा मालियती 6,72,61,266/रुपये वर दो किताह नान जुडिशियल कागज

हम कि श्री राजिन्द्र सिंह राणा आयु 55 साल पुत्र श्री ज्ञान चन्द पुत्र हमीर चन्द --- श्री प्रभात चन्द आयु 58 साल पुत्र चन्दू राम उपनाम झण्डू राम पुत्र नौधा निवासीगण नगारड़ा मौजा कोहला तहसील नादौन जिला हमीरपुर हि0 प्र0 --- श्री अजय कुमार आयु 46 साल पुत्र हरी राम पुत्र रोठल निवासी महाल बलोह मौजा हथोल तहसील नादौन जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के हैं जो कि भूमि खाता नम्बर 73 खतौनी नम्बर 78 खसरा नम्बर 1677 रकवा 02–68–84 है0 स्थित महाल कलूर मौजा कोहला तहसील नादौन जिला हमीरपुर हि0प्र0 अनुसार नकल जमाबन्दी साल 2021–2022 भाग बराबर भूमिपति हैं भूमि उपरोक्त 02–68–84 हैक्टेयर हिमाचल पथ परिवहन निगम हमीरपुर को बराये बस डिप्पो निर्माण हेतू चाहिए इसलिए भूमि उपरोक्त 02–68–84 हैक्टेयर को मये सर्वाधिकार बाहरी भीतरी काशतकारी मालगुजारी दरख्तान रास्ता व चरान्द व दीगर हक हकूक हर किस्म मुतलका के बदले मुबलिग रूपये 6,72,61,266 / छः करोड़ वहत्तर लाख इकसठ हजार दो सौ छयासठ रुपये आधे जिनके 3,36,30,633/–रुपये होते है पास हिमाचल पथ परिवहन निगम हमीरपुर को बिकी करके कब्जा केता को दिया गया केता जिस तरह चाहे लाम उठाये बिकी धन सालम मुबलिग 6,72,61,266/रुपये निम्न प्रकार से वसूल कर चुके हैं जिसका विवरण इस प्रकार है

Sr. No.	Name	Share	Land measuring	Check Number	Amount
1	Rajinder Singh Rana	1/3	00-89-61 hect.	309711	2,24,20,422/-
2	Prabhat Chand	1/3	00-89-61 hect.	309712	2,24,20,422/-
3	Ajay Kumar	1/3	00-89-62 hects	309713	2,24,20,422/-

अब कुछ लेना बाकी न रहा है उपरोक्त बिकीशुदा भूमि के इलावा मुजहर बाया के पास और भी भूमि शेष है मुजहरान भूमिहीन नहीं

SUB.REGISTRAR
NADAUN (H.P.)

Dy. Divisional Manager
HRTC Hamirpur (H.P.)

№ 1066091 2023 Himachal Government Judicial Paper

हो रहे हैं रकवा शहरी विकास योजना के अन्तर्गत नहीं आता है। मुताबिक हिमाचल पथ परिवहन निगम हमीरपुर आफिस आर्डर पत्र संख्या No.HP.BSM&DA/HMR/BUS Stand Nadaun/2023 दिनांक 14.12.2023 कापी साथ लफ है बैनामा इन्तकाल बिला उजर मन्जूर व तसदीक करवा देगें अतः यह चन्द शब्द बैनामा विलेख के रुप मे बकाईमी होश हवास खुद के तहरीर करवा देते हैं ताकि प्रमाणित रहे तिथि 06/01/2024 मुताबिक 15 पौष सम्वत 1945 शाका ।

अलवद श्री राजिन्द सिंह राणा बाया

अलवद श्री प्रभात चन्द बाया

अलवद श्री अजय कुमार बाया

साक्षी

अलवद हिमाचल पथ परिवहन निगम हमीरपुर वजिरिया राज कुमार उप मण्डलीय प्रबंधक HRTC Hamirpur (HP) केता

SUB.REGISTRAR
NADAUN (H.P.)

Dy. Divisional Manager
HRTC Hamirpur (H.P.)

उदयपुर में भीम सेतु राष्ट्र को समर्पित

केन्द्रीय रक्षा मंत्री ने डबल लेन पुल का किया उद्घाटन

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने जिला लाहौल-स्पिति के उदयपुर में नवनिर्मित डबल लेन पुल भीम सेतु को राष्ट्र को समर्पित करने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार व्यक्त किया।

यह पुल सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा बनाया गया है और क्षेत्र की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।

इस पुल का लोकार्पण समारोह बीआरओ के 66वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्यातिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने जिला बिलासपुर से वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण समारोह में शामिल हुए।

समारोह के दौरान रक्षा मंत्री ने अन्य राज्यों के लिए 50 सड़कों और पुलों सहित कई आधारभूत परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित किया। इनमें उदयपुर में 4.7 करोड़ रुपये की लागत से नवनिर्मित भीम सेतु भी शामिल है।

इस पुल का निर्माण 20 फरवरी, 2023 में शुरू हुआ था और 17 जनवरी, 2025 में यह बनकर तैयार हो गया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने इस पुल के सामरिक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह नया पुल 21 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है जिसकी भार क्षमता 70आर है तथा इससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी और परिवहन व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार होगा।

राज्यपाल ने प्रोजेक्ट दीपक के मुख्य अभियंता राजीव कुमार और उनकी पूरी टीम तथा 94 सड़क निर्माण कंपनी के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को इस शानदार उपलब्धि के लिए बधाई दी।

इससे पूर्व उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने राज्यपाल का स्वागत किया।

इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव सीपी वर्मा पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह, प्रोजेक्ट दीपक के मुख्य अभियंता राजीव कुमार सहित जिला प्रशासन एवं बीआरओ के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

राजभवन में मनाया गया विश्व रेडक्रॉस दिवस

शिमला/शैल। राजभवन में विश्व रेडक्रॉस दिवस की पूर्व संध्या पर राज्य रेडक्रॉस सोसायटी और हिमाचल प्रदेश रेडक्रॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग के सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने राज्यपाल एवं हिमाचल प्रदेश रेडक्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष शिव प्रताप शुक्ल तथा लेडी गवर्नर एवं प्रदेश रेडक्रॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्षा जानकी शुक्ला को रेडक्रॉस फ्लैग लगाए।

इस वर्ष विश्व रेडक्रॉस दिवस का विषय 'मानवता को जीवित रखना है' जो हमें यह संदेश देता है कि जरूरतमदों और पीड़ितों की मदद करना न केवल एक सामाजिक दायित्व है बल्कि हमारी मानवीय संवेदना का प्रमाण भी है।

राज्यपाल ने रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा वैश्विक स्तर पर किए जा रहे सेवा कार्य की सराहना करते हुए कहा कि यह संगठन पीड़ित मानवता के लिए आशा की किरण है। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि रेडक्रॉस सोसाइटी भविष्य में भी इसी तरह सेवा और समर्पण की भावना से कार्य करती रहेगी और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी।

राज्यपाल के सचिव व राज्य रेडक्रॉस सोसाइटी के महासचिव सीपी वर्मा, हिमाचल प्रदेश रेडक्रॉस और रेडक्रॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग के सदस्य सहित राजभवन के अधिकारी व कर्मचारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्यपाल ने हमीरपुर में अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस दिवस के राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आरम्भ ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के रूप में सामने आया है। उन्होंने भारतीय सेना की इस निर्णायक कारवाई की प्रशंसा की। राज्यपाल अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर हमीरपुर के मिनी सचिवालय परिसर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने अंतरराष्ट्रीय रेडक्रॉस दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रेडक्रॉस पीड़ित मानवता की सेवा के लिए समर्पित संस्था है। इसके निःस्वार्थ सेवा और प्रतिबद्धता ने इसे वैश्विक पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा कि यह दिन हम सभी को सेवा की भावना बनाए रखने की प्रेरणा देता है।

राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में रेडक्रॉस सोसायटी वंचितों के उत्थान तथा कल्याण के लिए सक्रिय रूप से कार्यरत है। उन्होंने नागरिकों से रेडक्रॉस से जुड़ने और मानवीय कार्यों में योगदान देने का आहवान किया। उन्होंने जिला में रेडक्रॉस प्रयोगशाला के पुनः संचालित होने पर संतोष व्यक्त किया, जिससे ज़रूरतमंद लोग लाभान्वित होंगे।

इससे पहले राज्यपाल ने सर्किट हाउस परिसर से ज़िला रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा आयोजित रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण और नशामुक्ति का संदेश देते हुए भाग लिया।

इस अवसर पर लेडी गर्वनर एवं राज्य रेडक्रॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्षा जानकी शुक्ला भी उपस्थित रहीं।

इसके उपरांत राज्यपाल ने डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में रेडक्रॉस प्रयोगशाला का पुनः शुभारम्भ किया। इस मौके पर उन्होंने रक्तदान शिविर का शुभारम्भ करने के अतिरिक्त मिनी सचिवालय परिसर में स्थापित ओपन एयर जिम का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने मिनी सचिवालय का भी दौरा किया तथा उपायुक्त से हाल ही में किए गए मरम्मत और अन्य सुधार कार्यों की जानकारी प्राप्त की।

इस अवसर पर उन्होंने शहीद कैप्टन मृदुल और भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेदकर की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की।

राज्यपाल ने इस अवसर पर विशेष रूप से सक्षम लोगों को कृत्रिम अंग वितरित किए और कला, खेल तथा अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया। उन्होंने रेडक्रॉस की रैफल ड्रॉ भी निकाला और विजेताओं की घोषणा की।

उपायुक्त एवं ज़िला रेडक्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष अमरजीत सिंह ने कहा कि रेडक्रॉस प्रयोगशाला के पुनः संचालन से ज़रूरतमंद लोगों को लाभ मिलने के अलावा अतिरिक्त आय भी सृजित होगी। उन्होंने कहा कि ज़िला में रेडक्रॉस के माध्यम से अनेकों गतिविधियां चलाई जा रही हैं। पिछले वर्ष से अब तक 17 नये संरक्षक और 135 आजीवन सदस्य रेडक्रॉस के साथ जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि अब ज़िला में रेडक्रॉस सदस्यों की संख्या 750 हो गई है।

पुलिस अधीक्षक भगत सिंह ठाकुर ने प्रदेश रेडक्रॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्षा जानकी शुक्ला को सम्मानित किया तथा ज़िला में नशामुक्ति की दिशा में चलाए जा रहे कार्यों से अवगत करवाया।

अतिरिक्त उपायुक्त तथा ज़िला रेडक्रॉस सोसाइटी के उपाध्यक्ष अभिषेक कुमार गर्ग ने ज़िला में रेडक्रॉस द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी।

सहायक आयुक्त अनुपम कुमार ने राज्यपाल का स्वागत किया।

इस अवसर पर 'पहचान' संस्था के विशेष रूप से सक्षम बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया।

हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा, सुजानपुर के विधायक रणजीत सिंह राणा, राज्यपाल के सचिव तथा राज्य रेडक्रॉस सोसाइटी के महासचिव सी.पी. वर्मा, ज़िला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

पांगी बनेगा राज्य का पहला प्राकृतिक खेती उप-मंडल

शिमला/शैल। सतत और रसायन मुक्त कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए, राज्य मंत्रिमंडल ने चंबा जिला के पांगी को राज्य का पहला प्राकृतिक खेती उप-मंडल घोषित करने को स्वीकृति प्रदान की है, इसका उद्देश्य राज्य में प्राकृतिक खेती पारिस्थितिकी प्रणाली को मजबूत करना है। प्रदेश सरकार द्वारा पांगी घाटी में प्राकृतिक खेती पद्धति अपनाने वाले किसानों को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) स्थापित किया जायेगा। यह संगठन प्राकृतिक पद्धति से उगाये गये उत्पादों के विपणन में सहायता प्रदान करने, फसल उत्पादन में अंतराल को दूर करने, प्राकृतिक उत्पादों की आपूर्ति और उत्पादन का समुचित प्रबंधन और उपज के लिए प्रभावी ग्रेडिंग, पैकेजिंग और बाजार लिंकेज सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि एफपीओ से किसानों को उनकी प्राकृतिक उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलने के साथ-साथ उपयुक्त बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर सीईटीआर एएनएफ प्रणाली के तहत किसानों के समूहों को विकसित और प्रमाणित किया जायेगा, इस प्रणाली को राज्य भर में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए अपनाया गया है।

इन प्रयासों से बड़े क्षेत्र प्रमाणन (एलएसी) का मार्ग प्रशस्त होगा, जिसमें एक ही क्षेत्र में रसायन-मुक्त खेती को अनिवार्य किया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, राज्य सरकार ने पांगी घाटी में भागीदारी गारंटी प्रणाली के तहत एलएसी प्रमाणन के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति को प्रमाणन प्रक्रिया शुरू करने के लिए विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया है।

प्राकृतिक खेती को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने पांगी क्षेत्र में प्राकृतिक खेती से उगाई गई जौ को 60 रुपये प्रति किलो ग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने की घोषणा की है। इस पहल से पांगी जैसे दुर्गम क्षेत्रों में स्थानीय युवा और कृषक वर्ग पर्यावरण हितैषी प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित होंगे और इन युवाओं को आजीविका का एक स्थाई साधन उपलब्ध होगा।

प्रवक्ता ने बताया कि यह कदम पांगी की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मील पत्थर साबित होगा। किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पांगी क्षेत्र में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए 5 करोड़ रुपये का रीवालिंवग फंड देने की घोषणा की है।

ईसीआई की राजनीतिक दलों के साथ सीधा संवाद पहल शुरू

शिमला/शैल। भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजनीतिक दलों के साथ सीधे संवाद की पहल शुरू की है। यह पहल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अधिक समावेशी और सहभागितापूर्ण बनाने के उद्देश्य से की गई है। इस संवाद के माध्यम से राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को आयोग के साथ सीधे अपनी समस्याओं, सुझावों और विचारों को साझा करने का अवसर मिल रहा है, जिससे पारदर्शिता और सहयोग को बढ़ावा मिल रहा है। इससे पूर्व आयोग द्वारा देशभर में 4,700 से अधिक सर्वदलीय बैठकों का आयोजन करवाया जा चुका है, जिनमें 28,000 से अधिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और निर्वाचन संबंधी विषयों पर व्यापक चर्चा की।

राज्य को मिले प्रतिष्ठित अधोसंरचना पुरस्कार मुख्यमंत्री ने टीम को बधाई दी

शिमला/शैल। सचिव लोक निर्माण विभाग और प्रबंध निदेशक हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड एचपीआर आईडीसीएल डॉ. अभिषेक जैन ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू

को अधोसंरचना विकास और सड़क सुरक्षा में हिमाचल प्रदेश की उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में प्राप्त दो ट्राफियां प्रस्तुत कीं।

एचपीआरआईडीसीएल को हाल ही में मोरक्को के माराकेच में प्रतिष्ठित 2024 आईआरएफ गैरी लिडल मेमोरियल ट्राफी में शाइनिंग स्टार से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सड़क प्राधिकरण को उच्च जोखिम वाली सड़कों को खत्म करने की दिशा में काम करने के लिए प्रदान किया जाता है। शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड को ढली सुरंग और सुरंग के बाहर रोटरी जंक्शन के निर्माण के लिए शहरी गतिशीलता में नवाचार श्रेणी के तहत स्मार्ट सिटीज़ इंडिया अवार्ड-2025 से सम्मानित किया गया है, जिससे शिमला में यातायात को सुचारु बनाए रखने में मदद मिली है।

मुख्यमंत्री ने दोनों संगठनों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके समर्पित प्रयासों के लिए बधाई दी और आशा व्यक्त की कि वे शिमला शहर के लोगों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान में इसी प्रतिबद्धता के साथ काम करना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पूरे राज्य में स्मार्ट, सुरक्षित और अधिक टिकाऊ शहरी और ग्रामीण अधोसंरचना के निर्माण में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी।

सुक्खू ने कहा कि एचपीआरआइ 'डीसीएल की सड़क सुरक्षा पहल प्रदेश के सम्पूर्ण विकास के प्रति एक समग्र और सौहार्दपूर्ण प्रयास का प्रतीक है जो विश्व बैंक हिमाचल प्रदेश पुलिस, लोक निर्माण विभाग, स्थानीय एजेंसियों और सामुदायिक स्वयंसेवकों के साथ संयुक्त रूप से कार्य कर रही है। यह पहल ठोस आंकड़ों पर आधारित सड़क सुरक्षा कार्य योजना के माध्यम से सड़क सुधारों को सफलतापूर्वक लागू करने में सहायता कर रही है, जिसके उत्कृष्ट परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल से विशेषकर राज्य के प्रमुख कॉरिडोर पर सड़क दुर्घटना में कमी दर्ज की गई है।

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सड़क सुरक्षा प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और यह गर्व की बात है कि हाल के समय में सड़क हादसों और मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य में सड़क सुरक्षा की स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए अन्तरराष्ट्रीय स्तर के उपाए अपनाए जा रहे हैं। इससे हिमाचल प्रदेश अन्य राज्य के लिए प्रेरणा बन कर उभरेगा।

एचपीआरआईडीसीएल के प्रबन्ध निदेशक अभिषेक जैन ने कहा कि अन्तरराष्ट्रीय सड़क मूल्यांकन कार्यक्रम आईपीएआर द्वारा प्रदान किए गए ये दोनों पुरस्कार एचपीआरआईडीसीएल के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि आईपीएआर संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान है। इस प्रतिष्ठित संस्थान से मान्यता प्राप्त करना एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि एचपीआरआईडीसीएल भविष्य में भी राज्य के लिए सुरक्षित और उच्च गुणवत्तायुक्त अधोसंरचना के विकास के लिए इसी प्रतिबद्धता से कार्य करता रहेगा।

ऑप्रेशन सिंदूर की सफलता के लिए सुरक्षा बलों को दी बधाई

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने भारतीय सेना द्वारा 'ऑप्रेशन सिंदूर' के सफल संचालन के उपरान्त एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।

मुख्यमंत्री ने 'ऑप्रेशन सिंदूर' के सफल संचालन के लिए भारतीय सशस्त्र बलों को बधाई देते हुए कहा कि हमें अपने देश की सेनाओं पर गर्व है।

उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था, खाद्यान्न आपूर्ति, संचार व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, आपदा प्रबन्धन, स्वास्थ्य सेवाएं सहित विभिन्न विषयों की विस्तृत समीक्षा की तथा विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था तथा विभिन्न प्रबन्धों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने सभी जिलों के उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों को जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए। बैठक में वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

रेडक्रॉस स्वयंसेवकों ने मुख्यमंत्री से भेंट की

शिमला/शैल। विश्व रेडक्रॉस दिवस-2025 के अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से बच्चों और रेडक्रॉस स्वयंसेवकों ने भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को रेडक्रॉस के स्टिकर भेंट किए। मुख्यमंत्री ने रेडक्रॉस कोष में योगदान दिया और लोगों से भी इस कोष में उदारतापूर्वक अंशदान का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रेडक्रॉस स्वयंसेवक मानवीय कल्याण के लिए बिना किसी लाभ के सदैव ही सराहनीय कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि का दिन विश्व भर के रेडक्रॉस स्वयंसेवकों के अथक प्रयासों को स्मरण करने एवं उनकी सेवाओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। यह स्वयंसेवक आपदा के समय जन सेवा के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़े रहते हैं। आपदा प्रभावितों को समय पर राहत सामग्री उपलब्ध करवाने और मुश्किल समय में उम्मीद की नई किरण भी प्रदान करते हैं।

इस अवसर पर उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, नगर निगम शिमला के पार्षदगण और हिमाचल प्रदेश रेडक्रॉस समिति के सदस्य उपस्थित थे।

प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करे शिक्षा विभाग:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में प्रधानाचार्य के पदों पर पदोन्नति के लिए प्रक्रिया अतिशीघ्र पूर्ण की जाए। उन्होंने कहा कि कर्मचारी कल्याण प्रदेश सरकार की प्राथमिकता सूची में शामिल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उन्हें समय पर लाभ प्रदान करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा क्षेत्र में अनेक सकारात्मक बदलाव ला रही है ताकि छात्रों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि शिक्षक सरकार के इस ध्येय को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सत्ता संभालने के उपरान्त शिक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के साथ-साथ छात्रों के विकास के लिए अनेक नवोन्मेषी पहल की हैं, जिनके फलस्वरूप राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की सराहना की जा रही है।

राज्य को पीएमजीएसवाई-3 के अन्तर्गत सड़कों और पुलों के लिए 3,345 करोड़ रुपये स्वीकृत: लोक निर्माण मंत्री

शिमला/शैल। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना-3 के अन्तर्गत राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। विभाग को 3,123 किलोमीटर

ग्रामीण सड़कों और 43 पुलों के निर्माण के लिए केन्द्र से 3,345 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हुई है।

विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि लोक निर्माण विभाग इन कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। राज्य में अब तक 517.334 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है, जिस पर 802.59 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। उन्होंने बताया कि यह ग्रामीण कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने तथा सड़क निर्माण कार्य को समयबद्ध पूर्ण करने की विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत 905 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जबकि 650 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था। उन्होंने बताया कि विभाग के बेहतर प्रदर्शन के दृष्टिगत राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से 2025-26 के लिए बजट आवंटन को बढ़ाकर 1300 करोड़ रुपये करने का आग्रह किया है।

उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग पीएमजीएसवाई-4 पर भी सक्रियता से कार्य कर रहा है। अब तक 1,560 आवासीय क्षेत्रों का मैपिंग कार्य पूरा हो चुका है, जिनमें से 1,115 आवासीय क्षेत्रों को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पात्र पाया गया है। इनमें 862 आवासीय क्षेत्रों को पहले ही मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इनमें चरण-1 के तहत 102 आवासीय क्षेत्र भी शामिल हैं।

विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के साथ 30 अप्रैल, 2025 को हुई बैठक के उपरांत, नेशनल रूरल्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी एनआरआइडीए की उच्च स्तरीय टीम ने 2 और 3 मई, 2025 को शिमला का दौरा किया। इस टीम ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की और पूर्व में अस्वीकृत किए गए 247 आवासीय क्षेत्रों के सत्यापन के बाद उनकी स्वीकृति पर पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया।

लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के पास 247 आवासीय क्षेत्रों में से 151 के लिए ही भूमि उपलब्ध है, जिसके लिए शीघ्र स्वीकृति का आग्रह किया गया है। राज्य स्वीकृति प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत लगभग 250 विस्तृत परियोजनाएं तैयार कर सकेगा, जिनमें 1400 किलोमीटर लंबी सड़कों का कार्य शामिल होगा। उन्होंने कहा कि यह कार्य समयबद्ध पूर्ण किया जाएगा।

विश्व रेडक्रॉस दिवस पर बधाई दी

शिमला/शैल। विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर राज्य रेडक्रॉस सोसायटी और अस्पताल कल्याण अनुभाग के सदस्यों, स्कूली बच्चों, रेडक्रॉस के कर्मचारियों व स्वयंसेवकों ने स्वास्थ्य मंत्री एवं अध्यक्ष, राज्य रेडक्रॉस प्रबन्धन समिति, डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल को बधाई दी और रेडक्रॉस का झंडा भेंट किया।

इस वर्ष विश्व रेडक्रॉस दिवस का थीम 'मानवता के पक्ष में' है जो मानवीय कार्यों में सहानुभूति और करुणा के महत्त्व पर बल देता है।

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पोर्टमोर और सम्भोटा, तिब्बतियन स्कूल छोटा शिमला के छात्र एवं छात्राओं ने भाग लिया। विद्यार्थियों ने अस्पताल कल्याण अनुभाग के सदस्यों के साथ आमजन को रेडक्रॉस के प्रति जागरूक करने के लिए रैली भी निकाली।

मनुष्य के रूप में हमारी सबसे बड़ी क्षमता दुनिया को बदलना नहीं है, बल्कि खुद को बदलना है

......महात्मा गांधी

सम्पादकीय

डोनाल्ड ट्रंप के दखल के मायने क्या हैं?

पहलगाम आतंकी हमले का जवाब देते हुये भारत ने पाक स्थित नौ आतंकी ठिकानों पर मिसाइल दागे और उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया। इसके लिये भारतीय सेना और देश का राजनीतिक नेतृत्व दोनों साधुवाद के पात्र हैं। भारत ने पाक के अन्दर घुसकर यह कारवाई की है। क्योंकि यह आतंकवाद पाक से संचालित और पोषित था। भारत-पाक के रिश्ते देश के विभाजन के समय से ही असहज हो गये थे। जब 1947 में ही यहां के कबाईलियों ने जम्मू-कश्मीर को अपने साथ मिलाने के लिये उस पर आक्रमण कर दिया था। तब वहां के राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। क्योंकि विभाजन के बाद यहां के राजाओं को अपनी इच्छा से भारत या पाकिस्तान किसी एक में विलय होने की छूट दी गयी थी। तब 1949 में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से युद्ध विराम हुआ और परिणाम स्वरुप जम्मू-कश्मीर का दो तिहाई भाग भारत का हिस्सा बन गया और पाक अधिकृत आजाद कश्मीर बन गया और उसे जनमत संग्रह से यह फैसला करने का अधिकार मिल गया कि वह किसके साथ जाना चाहता है। यह जनमत संग्रह कभी नहीं हुआ फिर भी भारत ने उसे विभाजन रेखा मान लिया। लेकिन अब आजाद कश्मीर तब से अब तक दोनों देशों के बीच एक समस्या बनकर खड़ा है। पाक इस क्षेत्र को अपने साथ मिलाने के लिये हर समय युद्ध और आतंकी वारदातों को प्रोत्साहित और संचालित करता रहता है। 1960 के दशक में दोनों देशों के बीच बड़े तनाव का परिणाम 1965 की लड़ाई है जिसमें पाकिस्तान हारा। इस हार के बाद जम्मू-कश्मीर में हिंसा भड़काने के ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया। इसका परिणाम 1971 के पाक विभाजन के रूप में सामने आया और शिमला समझौता हुआ।

लेकिन 1987 के चुनावों के बाद फिर हिंसा का दौर शुरू हो गया। कई उग्रवादी संगठन खड़े हो गये जिनमें जे.के.एल.एफ., लश्कर-ए तैयबा और एल.ई.टी प्रमुख है परिणामस्वरूप 1999 में दस सप्ताह तक संघर्ष चला। 2001 में संसद पर हमला हुआ जिसमें पांच आतंकी और 14 अन्य मारे गये। फिर 2008 में मुंबई में 166 लोग मारे गये। 2019 में सीआरपीएफ के 40 पुलिसकर्मी मारे गये। 2019 के अन्त में टी.आर. एफ. सामने आ गया और अब पहलगाम में 26 लोग मारे गये। यह कुछ मुख्य घटनाओं का विवरण है जो यह प्रमाणित करता है कि आतंकवाद लगातार दहशत का कारण बना रहा है। यह सही है कि हमारी सेनाओं ने हर बार सफलतापूर्वक इस आतंक को कुचला है। लेकिन यह अभी तक किसी न किसी शक्ल में सर उठाता ही रहा है। यह माना जा रहा है कि जब तक आजाद कश्मीर का स्थायी हल नहीं हो जाता है तब तक आतंकी घटनाएं किसी न किसी शक्ल में घटती ही रहेंगी। इस बार जिस तरह से पूरे विपक्ष में सरकार को समर्थन दिया और सरकार की ओर से यह संकेत और संदेश रहे कि अब आजाद कश्मीर भारत का हिस्सा बना दिया जायेगा उससे पूरा देश सेना के साथ खड़ा रहा। सेना लगातार सफल होती जा रही थी। लेकिन इस सफलता के बीच जिस तरह से युद्ध विराम घोषित हो गया और उस पर भी सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसकी सूचना दी यह अपने में एक नये संकट का संकेत है। क्योंकि इससे यह लगता है कि अमेरिका इसे एक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका का यह दखल कई अनकहे सवालों को जन्म दे जाता है। वह सारे सवाल जो पृष्ठभूमि में चले गये थे वह अब फिर से सामने आ जायेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस पर अभी तक चुप हैं। राहुल गांधी ने पत्र लिखकर सर्वदलीय बैठक और संसद का सत्र बुलाने की मांग की है। प्रधानमंत्री को संसद के सामने अमेरिका के दखल का खुलासा रखना चाहिये। क्योंकि देश ने इस ऑपरेशन में जान और माल की हानि झेली है। क्योंकि देश से यह वायदा किया गया था कि आतंक का स्थायी हल करके रहेंगे। इस हल के बिना युद्ध विराम क्यों आवश्यक हो गया यह देश के सामने रखना ही पड़ेगा।

युवा दायित्व के योगदान का उत्कृष्ट उदाहरण अनिकेत कुमार

युवा-दायित्व का समाज में सकारात्मक योगदान का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, चंबा नगर परिषद के तहत सुल्तानपुर मोहल्ले के युवा अनिकेत कुमार।

24 वर्षीय युवा अनिकेत कुमार अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के अनुरूप दसवीं कक्षा पास करने के पश्चात स्वरोजगार के माध्यम से अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाते हुए समाज में नशे के खिलाफ जागरूकता में भी अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं।

अनिकेत कुमार की दिनचर्या में एक तिपहिया वाहन के माध्यम से गन्ने का रस निकालकर उसे बेचना भी शामिल है।

अनिकेत कुमार बताते हैं कि सर्विस स्टेशन पर गाड़ियों को धोने का काम करने के बाद, वेल्डिंग, मैकेनिक आदि कार्य करते हुए उन्हें कुछ अलग करने की इच्छा हुई जो सहज भी हो और पैसा भी दिलाये तथा परिवार एवं मित्रों में बैठने का समय भी उपलब्ध करवाए।

उन्होंने बताया कि अपने प्रयासों को जारी रखते हुए सरकारी योजना स्वनिधि माइक्रो क्रेडिट से लाभ लेकर गन्ने का रस निकालने वाला तिपहिया वाहन खरीदा। आज 50 से 60 हजार रुपये प्रतिमाह कमा रहा हूं।

अनिकेत कुमार बताते हैं कि यह जमाना स्मार्ट वर्क का है। युवाओं के पास स्वरोजगार के बहुत से विकल्प हैं, साथ में सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं भी बहुत आसानी से उपलब्ध हैं।

स्थानीय मंदिर में सुबह और शाम अपनी सेवाएं देने वाले अनिकेत कुमार विशेषकर युवाओं को नशे से घातक दुष्प्रभावों की जानकारी भी प्रदान करते हैं।

उनका यह भी कहना है कि यदि हम छोटे-छोटे स्तर पर ईमानदारी से प्रयास करें, तो समाज में बड़े और सकारात्मक परिवर्तन लाये जा सकते हैं। उन्होंने युवाओं से आहवान किया कि वे अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए समाज में सकारात्मक बदलाव के प्रेरक बनें।

राजमिस्त्री के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बोर्ड ने प्रदान की 84 हजार रुपये की आर्थिक सहायता

दीवारों पर ईट-गारा लगाते जो हाथ दिन-रात मेहनत में रमे रहते हैं, उन्हीं हाथों ने अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य का सपना भी गढ़ा है। करसोग की उप-तहसील बगशाड के रंडौल गांव के राजमिस्त्री लीला नंद के लिए बच्चों को ऊंची शिक्षा दिलाना एक ऐसा सपना था, जिसे उन्होंने कभी खुली आंखों से देखने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड ने लीला नंद के सपने को न सिर्फ हकीकत में बदला, बल्कि उनके बेटे और बेटी को आत्मनिर्भर बनने की राह पर भी आगे बढ़ाया।

लीला नंद ने हिमाचल प्रदेश भवन

एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में वर्ष-2023 में पंजीकरण करवाया था। पंजीकरण के उपरांत, बोर्ड की ओर से उनके बच्चों को शिक्षा के लिए लगभग 84 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि बोर्ड की ओर से उनके बेटे साहिल को इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आईटीआई की पढ़ाई के लिए 48 हजार रुपए और उनकी बेटी अंजली को ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए 36 हजार रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की गई।

उन्होंने बताया कि बोर्ड की ओर से मिली इस आर्थिक मदद से बेटे साहिल ने शिमला के पंथाघाटी से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में सफलतापूर्वक अपना आईटीआई कोर्स उत्तीर्ण किया है और आज वह एसजेवीएनएल में अप्रेंटिसशिप कर रहा है। वहीं, उनकी बेटी अंजली ने 36,000 रुपए की इस आर्थिक मदद से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। यह आर्थिक सहायता उनके उज्ज्वल भविष्य की ओर एक मजबूत कदम साबित हुई।

ऐसे व्यक्ति जो किसी भवन या निर्माण कार्य में कुशल, अर्द्धकुशल के रूप में या मैनुअल, लिपिकीय कार्य, सुपरवाईजर या तकनीकी, वेतन या पारिश्रमिक के लिए कार्य करते है। जैसा कि मिस्त्री, पेंटर, प्लम्बर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, मजदूर व हेल्पर आदि कामगार की श्रेणी में आते हैं और हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

राज्य सरकार ऐसे श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। बोर्ड के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को समय-समय पर आर्थिक मदद प्रदान की जा रही है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। जिसके अन्तर्गत लीला नंद के बच्चों को भी आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के संवेदनशील नेतृत्व में प्रदेश सरकार का यह संकल्प है कि कोई भी होनहार बच्चा केवल संसाधनों की कमी के कारण अपने सपनों से वंचित न रहे। कामगार कल्याण बोर्ड जैसे प्रयास इसी दिशा में एक मजबूत कड़ी हैं, जो राज्य के निर्माण में लगे मजदूरों को सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, सम्मान और संभावनाओं से भरा भविष्य भी देते हैं।

लीला नंद का कहना है, अगर सरकार की आर्थिक मदद नहीं मिलती तो बच्चे पढ़ नहीं पाते। आज उन्हें आगे बढ़ते देख कर लगता है कि मेहनत रंग लायी है। उनका कहना है कि यह कहानी न केवल एक परिवार की सफलता का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि सरकारी योजनाएं जब ज़रूरतमंदों तक पहुंचती हैं, तो वे जीवन को संवार सकती हैं।

साहिल व अंजली ने बताया कि हमारे पिता जी ने हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में अपना पंजीकरण करवाया है। जिसके उपरांत प्रदेश सरकार द्वारा हमारी पढ़ाई-लिखाई के लिए, हमें आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। अंजली ने बताया कि इस मदद से उन्होंने डिग्री कॉलेज सुन्नी से अपनी बी.ए. की पढ़ाई पूरी कर ली है। हम जैसे गरीब लोगों के लिए यह एक बहुत अच्छी योजना है। सरकार ने हमें जो आर्थिक सहायता प्रदान की है उसी से हम अपनी पढ़ाई पूरी कर पाए हैं। इसके लिए हम प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हैं जो हम जैसे जरूरतमंद लोगों के बारे में सोचते हैं।

देश का आईटी हब बनकर उभरेगा हिमाचल

शिमला। हिमाचल प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संभावनाओं के नये द्वार खुल रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुशल कार्यबल की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में देश को कुशल कार्यबल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हिमाचल सरकार ने अभिनव पहल की है।

प्रदेश सरकार राज्य में नवाचार को बढ़ावा दे रही है। इसके दृष्टिगत समग्र ड्रोन इको सिस्टम की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। ड्रोन प्रौद्योगिकी कृषि, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाती है। ग्रीन हिमाचल विजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में ड्रोन प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना नितांत अनिवार्य है।

वर्तमान इस वित्त वर्ष के दौरान लोगों को ड्रोन टैक्सी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कार्य योजना बनाई जा रही है, इससे प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पाद और दवाइयां इत्यादि की आपूर्ति करने में सहायता मिलेगी। ड्रोन टैक्नोलॉजी इंटरवेंशन से कृषि और बागवानी क्षेत्रों में आधुनिकीकरण के दृष्टिगत जिला हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा में ड्रोन स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

ड्रोन प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार युवाओं के लिए स्वरोजगार और रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से वर्ष 2024-25 में राज्य के 243 युवाओं ने ड्रोन से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

युवाओं को ड्रोन प्रौद्योगिकी में दक्ष बनाने के साथ-साथ अब राज्य में न्यू एज पाठ्यक्रमों का समावेश भी किया जा रहा है। इस दिशा में जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवां में राजीव गांधी राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस का नया महाविद्यालय, जिला शिमला के प्रगति नगर में अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में सिविल इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स, जिला मंडी के राजकीय पॉलिटेक्निकल सुन्दरनगर में कम्प्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग (एआई एण्ड मशीन लर्निंग) का डिप्लोमा कोर्स शुरू करने को स्वीकृति प्रदान की है। इन पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए आवश्यक स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित जाएगी।

एआई और डाटा साइंस क्षेत्र में वर्तमान में अपार संभावनाएं है। इन क्षेत्रों में युवाओं का कौशल उन्नयन कर उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

राज्य में नवाचार संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दो करोड़ रुपये के इनोवेशन फंड की स्थापना की जाएगी, जिसके माध्यम से प्रदेश के युवा अपनी नवाचार पहलों को साकार रूप प्रदान कर सकेंगे। जिला बिलासपुर के घुमारवीं में सार्वजनिक निजी भागीदारी व सैल्फ फाइनांसिंग आधार पर डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ इनोवेशन, इन्टरप्रेन्योरशिप, स्किल एण्ड वोकेशनल स्टडीज की स्थापना की जाएगी। इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से युवाओं को नवाचार और इन्टरप्रेन्योरशिप स्किल को निखारा जाएगा।

प्रदेश सरकार सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युवाओं के लिए नवाचार और स्वरोजगार के नए द्वार खोल रही है। सरकार के इन प्रयासों से हिमाचल निश्चित रूप से देश का आईटी हब बनकर उभरेगा।

दुग्ध उत्पादन में युवा उद्यमी के ज़ज्बे ने लिखी सफलता की नई इबारत

शिमला। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हो, कठिन परिश्रम व सच्ची लगन, व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुंचा ही देती है। यह साबित किया है तुंगल क्षेत्र की युवा उद्यमी सकीना ठाकुर ने। इतिहास की छात्रा रही सकीना अपने ज़ज्बे एवं नवोन्मेषी प्रयासों से आज दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच रही हैं।

कोटली उपमंडल के कून गांव में एक साधारण परिवार में जन्मीं सकीना ठाकुर की बचपन से ही उद्यमी सोच रही है। कोट के सरकारी स्कूल से शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत मंडी शहर में उच्च शिक्षा के लिए चली आयी। यहां राजकीय वल्लभ डिग्री कॉलेज से उन्होंने इतिहास विषय में एम.ए. की उपाधि प्राप्त की। वह बताती हैं कि मंडी में घर पर जो दूध आता, वह काफी पतला व निम्न गुणवत्ता का था। वहीं से उन्हें विचार आया कि वे किस तरह लोगों को उच्च गुणवत्ता का दूध उपलब्ध करवा सकती हैं। हालांकि जिम, मॉडलिंग व बॉक्सिंग में करियर बनाने के सपने भी मन में हुलारे मार रहे थे। मगर, परिवार सरकारी नौकरी के लिए दबाव डाल रहा था। इन तमाम विरोधाभासों के बीच सकीना ने कुछ समय स्वास्थ्य विभाग की परियोजना में सर्वेक्षणकर्ता के रूप में भी कार्य किया।

वह बताती हैं कि इस नौकरी से संचित धन उन्होंने दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में निवेश करने का मन बना लिया। शुरुआत बेहद चुनौतीपूर्ण रही, क्योंकि घर-परिवार से लेकर गांव-चौबारे तक हर जगह सहयोग की अपेक्षा ताने ही अधिक मिल रहे थे। एक शिक्षित लड़की कैसे गाय-गोबर का काम करेगी, इस तरह के उलाहने उन्हें परेशान तो करते, मगर लक्ष्य पर केंद्रित रहकर ऐसी सोच को गलत साबित करने का जरिया भी बन रहे थे।

दुग्ध उत्पादन में आगे बढ़ने का हौसला उन्हें पड़ोसी गांव भरगांव की चिंता देवी ने दिया। यू-ट्यूब से भी डेयरी क्षेत्र की जानकारी प्राप्त की। इसके बाद पंजाब में भठिंडा के समीप गुरविंदर डेयरी फार्म से होलस्टीन फ्रिजियन (एचएफ) नस्ल की गाय खरीदी। यूरोपियन नस्ल की इन गाय के दूध में प्रोटीन व मक्खन भरपूर मात्रा में होता है। अलग-अलग जलवायु में अनुकूलनशीलता और उत्पादकता में भी यह नस्ल बेहतर होती है।

डेयरी व्यवसाय में पूंजी जुटाने के लिए भी सकीना ने कई माध्यम अपनाये। हाथ में मात्र सवा लाख रुपए के करीब ही बचत थी, मगर हौसला पहाड़ों से भी ऊंचा। ऐसे में ग्रामीण बैंक से लगभग दो लाख रुपए का ऋण लिया और जुलाई, 2024 में सकीना डेयरी फार्म की शुरुआत कर दी। अब मां रमा देवी व भाई-बहन का साथ भी मिला।

प्रदेश सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादन को निरंतर प्रोत्साहन से भी सकीना जैसे युवा उद्यमियों को काफी संबल मिला है। सकीना बताती हैं कि नवंबर, 2024 में उनके गांव में द कून महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का कार्यालय खुला और यहां हिमाचल प्रदेश राज्य दुग्ध उत्पादक प्रसंघ की ओर से तमाम सुविधाएं एवं उपकरण इत्यादि उपलब्ध करवाए गए। यहां दो क्विंटल क्षमता का बल्क मिल्क कूलर, एसएनएफ एनालाइजर, अल्ट्रासोनिक स्टरर, कम्प्यूटर इत्यादि स्थापित हैं। सकीना यहां दुग्ध प्रापण का कार्य देख रही हैं।

वर्तमान में सकीना अपने फार्म से लगभग 112 लीटर (1.12 क्विंटल) दूध प्रतिदिन प्राप्त कर रही हैं। फार्म में वह एचएफ नस्ल की 14 गायें पाल रही हैं। लगभग साढ़े चार लाख रुपए की लागत से एक आधुनिक शेड का भी निर्माण किया है। पशु चारा स्थानीय स्तर के साथ ही पंजाब से भी ला रही हैं। मिल्किंग मशीन व चारा कटर पर करीब 50 हजार रुपए निवेश किये हैं। गोबर खाद के रूप में उपयोग हो रहा है। फार्म में एक व्यक्ति को रोजगार भी दिया है। बतौर सकीना उन्हें प्रतिमाह लगभग सवा लाख रुपए तक आय हो रही है। उनकी सोसायटी से कून के अलावा कोट, लंबीधार, ड्रुब्बल, त्रैहड़, माहन इत्यादि गांवों के लगभग 70 परिवार जुड़ चुके हैं। इन्हें मिलाकर सहकारी समिति की आय दो लाख रुपए प्रतिमाह तक पहुंच रही है।

राज्य सरकार द्वारा दूध के खरीद मूल्य में बढ़ौतरी से यहां किसानों की आय भी बढ़ी है और हौसला भी। बकौल सकीना उन्हें दूध की गुणवत्ता के अनुरूप 41 से 44 रुपए प्रति लीटर का दाम मिल रहा है। इस साल गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 51 रुपए करने के लिए सकीना ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू का आभार जताया है।

ग्राम पंचायत उपप्रधान विजय कुमार ने कहा कि सकीना ठाकुर समाज के लिए एक उदाहरण हैं। इस युवा उद्यमी ने साबित किया है कि कोई भी कार्य छोटा-बड़ा अथवा कठिन नहीं होता। ग्रामीण स्तर तक दुग्ध समितियां स्थापित करने के लिए उन्होंने राज्य सरकार का भी आभार जताया है।

युद्ध, आतंक एवं भारतीय आपदा प्रबंधन व्यवस्था

राजन कुमार शर्मा
आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ

दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित भारत एक शांतिपूर्वक देश है। यह शांति के प्रतीक महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, महावीर, और आदि गुरु शंकराचार्य की जन्मस्थली व तपोभूमि रही है। इस देश का शुरू से ही मानना है कि किसी भी प्रकार का युद्ध चाहे वह विश्व युद्ध, आंतरिक युद्ध या आतंकवादी गतिविधियां हो, उससे किसी भी राष्ट्र की प्रगति, विकास, नागरिक सुरक्षा, आर्थिक, सामाजिक व मानसिक विकास, सांस्कृतिक प्रगति संभव नहीं हो सकती है। आए दिन पड़ोसी देश पाकिस्तान द्वारा संरक्षित आतंकवादी लॉन्च पैड व शिविरों से मासूम लोगों की शांति व सुरक्षा पर सवाल उठते रहे हैं। हाल ही में अप्रैल के महीने में जम्मू कश्मीर के पहलगाम पर्यटन स्थल पर 26 भारतीय पर्यटकों को आतंकवादियों द्वारा निर्मम रूप से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस कृत्य से संपूर्ण भारत के नागरिकों में कड़ी निंदा व रोष की लहर उठ गई थी। इस आतंकवादी हमले की प्रतिक्रिया के रूप में आज 7 मई को रक्षा मंत्रालय द्वारा सूचित कर बताया गया कि सैन्य ऑपरेशन सिंदूर द्वारा मध्य रात्रि में पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित इन आतंकवादियों के लगभग 9 लॉन्च पैड्स व शिविरों को पूर्णतया ध्वस्त कर दिया गया है। ज्ञात रहे कि आज 7 मई शाम 4:00 बजे गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन अभ्यास द्वारा पूर्व प्रस्तावित कुछ चुनिंदा नागरिक सुरक्षा शहरों व राज्यों में मौक अभ्यास भी आयोजित करवाया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के हवाई हमले व अन्य तरह के युद्ध जैसी स्थिति में नागरिकों, स्कूली बच्चों एवं अन्य प्रतिक्रिया एजेंसियों को पूर्ण रूप से जागरूक व साथ ही प्रशिक्षित भी किया जा सके। भारत में आपदा प्रबंधन विभाग, केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत है तथा इस तरह की घटनाओं में योजना, समीक्षा व कार्यान्वयन करने का जिम्मा इसी को जाता है: आईए इसकी रूपरेखा के बारे में समझें: आपदा प्रबंधन जिसमें विभिन्न प्रकार की आपदाओं जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं भूकंप, बाढ़, चक्रवात आदि और मानव-जनित आपदाएं दंगे, आतंकवादी हमले आदि से निपटने के लिए रणनीतियों और योजनाओं का विकास किया जाता है।

आपदा प्रबंधन के मुख्य घटक हैं:

1. आपदा रोकथाम आपदा के प्रभावों को कम करने के लिए कदम उठाना।
2. आपदा तैयारी: आपदा के समय तैयार रहने के लिए योजनाएं बनाना और अभ्यास करना।
3. आपदा प्रतिक्रिया: आपदा के समय तेजी से और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करना।
4. आपदा पुनर्वास: आपदा के बाद पुनर्वास और पुनर्निर्माण के प्रयास करना।

भारत में आपदा प्रबंधन के लिए विभिन्न संस्थाएं और एजेंसियां काम करती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं

1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए: आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों और योजनाओं का विकास करना।
2. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए: राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए काम करना।
3. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए: जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए काम करना।

आपदा प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें स्थानीय समुदायों को आपदा के समय अपनी सुरक्षा और बचाव के लिए तैयार रहने के लिए जागरूक किया जाता है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश अत्यधिक जनसंख्या वाले देश हैं, तथा दोनों ही देशों के पास परमाणु हथियार व आधुनिक तकनीक के उपकरण, युद्ध कौशल विकसित है, यह कहना उचित होगा कि भविष्य में इस तरह के तनाव उत्पन्न होने पर युद्ध जैसी स्थिति का सामना दोनों देशों को करना पड़ सकता है तथा इससे बचने हेतु पूर्ण रूप से तैयारी जागरूकता व आत्मविश्वास महत्वपूर्ण है। भारत की अत्यधिक आबादी के मध्यनजर यहां पर आपदा संवेदनशीलता अत्यधिक है जिस की नजर अंदाज नहीं किया जा सकता तथा युद्ध जैसी स्थिति के दौरान अत्यधिक जान व माल के नुकसान होने की संभावना भी है, इसीलिए प्रत्येक नागरिक को नागरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, सुरक्षित निकासी, सुरक्षित भवन, प्राथमिक प्रशिक्षण, प्राथमिक चिकित्सा उपचार, आपदा किट, आपातकालीन दूरभाष नंबर व भूमिगत सुरक्षित बंकरों का निर्माण तैयारी के मध्यनजर समय रहते कर लेना चाहिए। क्योंकि तैयारी में ही समझदारी है तथा समय रहते यदि हम जागरूक होंगे तो ही इस तरह के हवाई हमले व अन्य युद्ध जैसी स्थितियों से बच पाने में कारगर साबित होंगे। हालांकि संयुक्त राष्ट्र दोनों ही देशों से शांति एवं युद्ध तनाव को दूर करने के संबंध में आग्रह कर रहा है, ताकि 80 वर्ष बाद संसार को कोई और विश्व युद्ध न झेलना पड़े।

घरेलू कार्य करने वाली महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में शामिल करने का निर्णय

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में घरेलू कार्य करने वाली महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया। जिन महिलाओं ने घरेलू सहायिका के रूप में न्यूनतम 100 दिन कार्य किया है, वह महिलाएं अब इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी। इसके अलावा इन महिलाओं की 21 वर्ष या उससे अधिक आयु की बेटियां भी इस योजना के तहत पात्र होंगी और उन्हें 1500 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे।

मंत्रिमंडल ने राज्य में प्राकृतिक पद्धति से तैयार की गई फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दी है। इस पद्धति से तैयार गेहूं के एमएसपी को 40 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये तथा मक्की के एमएसपी को 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, प्राकृतिक रूप से उगाई गई कच्ची हल्दी के लिए 90 रुपये प्रति किलोग्राम और जिला चंबा के पांगी खंड में उगाए गए जौ के लिए 60 रुपये प्रति किलोग्राम एमएसपी को मंजूरी प्रदान की गई है। पांगी को राज्य का पहला प्राकृतिक खेती उप-मंडल घोषित करने का भी निर्णय लिया गया।

बैठक में राज्य के लोगों को बेहतर परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाने और बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए निजी आपॅपरेटरों को 422 स्टेज कैरिज रूट आवंटित करने को मंजूरी दी गई।

मंत्रिमंडल ने सड़कों के किनारे गाड़ियां पार्क करने और ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए जहां व्यवहारिक हो उन बंद बेसमेंट फ्लोर को पार्किंग सुविधा के लिए खोलने को मंजूरी दी। यदि निर्धारित पार्किंग फ्लोर का उपयोग पार्किंग के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया गया तो उल्लंघनकर्ता पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और फ्लोर को पार्किंग के लिए बहाल करना होगा।

मंत्रिमंडल ने डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में नेफोलॉजी, न्यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभागों को आरंभ करने तथा उनके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 118 पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी दी।

बैठक में राज्य के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों के अंतर्गत 43 विभिन्न तकनीकी पदों को भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिला के सुजानपुर में जल शक्ति विभाग का एक नया मंडल खोलने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने नई होमस्टे नीति को मंजूरी दी तथा चंबा जिला के पांगी उप-मंडल में होमस्टे के लिए पंजीकरण शुल्क मानक दर का 50 प्रतिशत निर्धारित करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के कोसरी में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र को 10 बिस्तरों वाले आयुर्वेदिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को भी मंजूरी दी।

इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने ऊना जिला के पंजावर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने और आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने नवगठित 14 नगर पंचायतों तथा हमीरपुर, ऊना एवं बद्दी के स्तरोन्नत नगर निगमों के विलय किए गए क्षेत्रों के साथ-साथ नादौन एवं बैजनाथ-पपरोला नगर परिषदों के निवासियों को जल शुल्क में राहत प्रदान करने का निर्णय लिया। इस निर्णय में हाल ही में ज्वालामुखी, देहरा, पांवटा-साहिब नगर परिषदों तथा ज्वाली नगर पंचायत में विलयित क्षेत्र भी शामिल हैं। इन क्षेत्रों में अगले तीन वर्षों तक ग्रामीण दरों पर जल शुल्क लिया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने सात स्टेट ऑफ आर्ट एसओए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई को अन्य आईटीआई में और सात महिला आईटीआई को राज्य के अन्य विभिन्न आईटीआई में विलय करने की मंजूरी दी। एसओए राजकीय आईटीआई घुमारवीं का राजकीय आईटीआई घुमारवीं, एसओए राजकीय आईटीआई गरनोटा का राजकीय आईटीआई गरनोटा, एसओए राजकीय आईटीआई शमशी का राजकीय आईटीआई शमशी, एसओए राजकीय आईटीआई सुन्नी का राजकीय आईटीआई सुन्नी, एसओए राजकीय आईटीआई नाहन, पांवटा साहिब, का राजकीय आईटीआई नाहन, एसओए राजकीय आईटीआई गगरेट का राजकीय आईटीआई भद्रकाली और एसओए राजकीय आईटीआई सुन्दरनगर का राजकीय आईटीआई पीडब्ल्यूडी सुंदरनगर में विलय किया गया है। मंत्रिमंडल ने राजकीय आईटीआई बिलासपुर महिला का राजकीय आईटीआई बिलासपुर, राजकीय आईटीआई नाहन महिला का राजकीय आईटीआई नाहन राजकीय आईटीआई चंबा महिला का राजकीय आईटीआई चंबा, राजकीय आईटीआई रिकांगपिओ महिला का राजकीय आईटीआई रिकांगपिओ, राजकीय आईटीआई मंडी महिला का राजकीय आईटीआई मंडी, राजकीय आईटीआई शिमला महिला का राजकीय आईटीआई शिमला और राजकीय आईटीआई ऊना महिला का राजकीय आईटीआई ऊना में विलय को स्वीकृति दी।

भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने का आह्वान:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने संभोटा तिब्बती स्कूल में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। वैशाख पूर्णिमा और भगवान बुद्ध की जयंती के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री ने

शुभकामनाएं देते हुए भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करने का आहवान किया ताकि एक सशक्त समाज का निर्माण हो सके। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध ने हमें 'अप्प दीपो भव' का मंत्र दिया, जिसका अर्थ है 'स्वयं अपने दीप बनो'। यह आत्मनिर्भरता का मूल मंत्र है, जो आज के युग में भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में हमारा मार्गदर्शन करता है।

उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी प्राचीन काल में थीं। हिंसा, असहिष्णुता और अविश्वास से भरे इस युग में भगवान बुद्ध द्वारा दिया गया शांति, करुणा और सहिष्णुता का संदेश मार्ग दिखाता है। ये महज शिक्षाएं नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान और 'महापरिनिर्वाण' इसी दिन हुआ था। एक ही दिन में ये तीन महान घटनाएं इस दिन को बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण बनाती हैं। भगवान बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि करुणा, शांति और मानवता ही सच्चे धर्म के मूल स्तम्भ हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में, जहां भौतिक सुख-सुविधाएं तनाव और असंतुलन का कारण बनती है, ऐसे में भगवान बुद्ध का संदेश हमें शांति, सद्भाव और सच्चे सुख का मार्ग दिखाता है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने त्सेरिंग पलकत नेगी और पेमा दोरजे को भारत-तिब्बत मैत्री अवार्ड से सम्मानित किया।

विधायक हरीश जनारथा, महापौर सुरेंद्र चौहान, उप-महापौर उमा कौशल, तिब्बती निर्वासित सरकार के प्रमुख प्रतिनिधि लहाक्पा त्सेरिंग, उपायुक्त अनुपम कश्यप और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

किसानों को 4.04 रुपए प्रति यूनिट सब्सिडी देने की अधिसूचना जारी

शिमला/शैल। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध करवाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों को केवल एक रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार प्रति यूनिट 4.04 रुपये की सब्सिडी वहन करेगी, जिसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि अधिसूचना जारी होने में थोड़ी देरी के कारण कुछ किसानों को अस्थायी रूप से बढ़ी हुई दरों पर बिजली बिल मिले हैं। हालांकि, उन्होंने आश्वासन दिया कि किसानों से अतिरिक्त वसूल की गई राशि को आगामी बिलों में समायोजित कर राहत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और इस दिशा में सभी आवश्यक व प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।

एक वर्ष में पूरी होगी करूणामूलक आधार पर लम्बित भर्ती प्रक्रिया:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने करूणामूलक आधार पर लम्बित रोजगार संबंधी मामलों की प्रक्रिया को एक वर्ष के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री करूणामूलक रोजगार नीति पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन भर्तियों की पात्रता के लिए वार्षिक आय सीमा को 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये किया जाएगा। करूणामूलक आधार पर लम्बित मामलों को तीन चरणों में निपटाया जाएगा। पहले चरण में विधवा तथा 45 वर्ष से कम आयुवर्ग के उन आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनके माता-पिता नहीं है। वर्तमान में प्रदेश में इस श्रेणी में 141 विधवाएं और 159 अनाथ बच्चे शामिल हैं।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि दूसरे चरण में कम वार्षिक आय वाले पात्र व्यक्तियों को करूणामूलक आधार पर रोजगार प्रदान किया जाएगा तथा शेष पात्र आवेदकों को तीसरे चरण में नौकरी दी जाएगी।

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा, प्रधान सचिव देवेश कुमार, सचिव एम. सुधा देवी और राकेश कंवर तथा सचिव विधि शरद कुमार लगवाल बैठक में उपस्थित थे।

मंत्रिमंडल की बैठकों में लिए गए 789 निर्णय पूरी तरह कार्यान्वित:जगत सिंह नेगी

शिमला/शैल। राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयुष, युवा सेवाएं एवं खेल तथा विधि मंत्री यादविंद्र गोमा भी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्रिमंडल की बैठकों में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन को लेकर समीक्षा की गई।

बैठक में अवगत करवाया गया कि 13 जनवरी, 2023 से 31 दिसंबर, 2024 तक मंत्रिमंडल की बैठकों में 831 निर्णय लिए गए, जिनमें से 789 निर्णयों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा चुका है। शेष बचे 42 निर्णयों को लेकर चर्चा की गई, जिनमें जलशक्ति, कृषि, वित्त, बागवानी, कार्मिक और लोक निर्माण विभाग से जुड़े निर्णय शामिल हैं।

जगत सिंह नेगी ने अधिकारियों को इन निर्णयों को समयबद्ध कार्यान्वित करने के निर्देश दिए ताकि आम जनता को लाभ मिल सके।

बैठक में सदस्य सचिव हरबंस सिंह ब्रसकोन और संयुक्त सचिव सामान्य प्रशासन विभाग कुलविंद्र सिंह भी उपस्थित रहे।

नये अधिसूचित शहरी क्षेत्रों को पानी शुल्क और संपत्ति कर में छूट

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने प्रदेश में हाल ही में नवगठित और अपग्रेड हुए शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के अंतर्गत आने वाले लोगों को बड़ी राहत प्रदान की है। उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में आगामी तीन वर्षों तक जल आपूर्ति की दरें ग्रामीण दरों पर ही लागू रहेंगी। यह निर्णय हाल ही शहरी स्थानीय निकायों में शामिल लोगों को सुगम और सहज रूप से शहारी व्यवस्था में शामिल करने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने बताया कि इस निर्णय से प्रदेश भर के 47,820 उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। पानी शुल्क में रियायत के अलावा इन क्षेत्रों के निवासियों को संपत्ति कर में भी छूट प्रदान की गई है।

हाल ही में किए गए प्रशासनिक पुनर्गठन के अंतर्गत सरकार ने प्रदेश में 14 नई नगर पंचायतें गठित की हैं, जिनमें संधोल, धर्मपुर, बलद्वाड़ा, बनीखेत, खुंडियां, कोटला, नगरोटा सूरियां, कुनिहार, झण्डूता, स्वारघाट, बड़सर, भराड़ी, बंगाणा और शिलाई शामिल हैं। इसके अतिरिक्त हमीरपुर, ऊना और बद्दी को नगर निगमों में अपग्रेड किया गया है, जबकि नादौन और बैजनाथ-पपरोला को नगर परिषदों का दर्जा प्रदान किया गया है। इसके परिणामस्वरूप कई नए क्षेत्र अब शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के अधिकार क्षेत्र में शामिल हुये हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि यह निर्णय शहरी निकायों के पुनर्गठन के कारण यहां रहने वाले लोगों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ से राहत प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। इस निर्णय से शहरी निकायों के पुनर्गठन के दौरान इन क्षेत्रों में शामिल होने वाले लोगों का जीवन स्तर प्रभावित नहीं होगा। पानी की दरों में रियायत और संपत्ति कर में छूट से इन क्षेत्रों के निवासी बिना किसी अतिरिक्त आर्थिक दबाव के जीवनयापन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से न केवल लोगों को राहत मिलेगी बल्कि इन्हें बेहतर बुनियादी सुविधाएं भी सुनिश्चित होंगी।

शहरों में पानी की दरो में 500 प्रतिशत की बढ़ौतरी:बिंदल

शिमला/शैल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिन्दल ने कहा कि सरकार के द्वारा प्रतिदिन लिये जा रहे फैंसलो से प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है। हिमाचल प्रदेश का कोई

भी वर्ग ऐसा नहीं छूटा जिसके उपर सुखविन्द सिंह सुक्खू सरकार ने टैक्स न लगाया हो और ये टैक्स की मार प्रदेश की जनता को हजारों करोड़ रूपये में पड़ रही है। डॉ. बिन्दल ने कहा कि सत्ता में आते ही कांग्रेस ने डीजल पर 7.50 रूपये लीटर टैक्स लगाया और विगत ढाई साल में लगभग 4000 करोड़ रूपये का टैक्स हिमाचल प्रदेश की जनता से वसूला जा चुका है। 2022 के चुनाव में कहा था कि बिजली फ्री करेंगे, फ्री तो क्या करनी थी, हर व्यक्ति को मिलने वाली 125 युनिट फ्री बिजली भी बंद कर दी। बिजली में अनेक टैक्स लगाकर बिजली के दामो में भारी वृद्धि कर दी।

प्रदेश में ग्रामीण लोगों को पानी मुफ्त में मिल रहा था, उस पर भी टैक्स लगा दिया और शहरों में मिलने वाले पानी की दरो में 500 प्रतिशत की बढ़ौतरी कर दी गई। राशन के डिपु में मिलने वाले आटे का दाम 3 रूपये और चावल का दाम 4.50 रूपये और सरसों के तेल के दाम में 50 रूपये से अधिक की बढ़ौतरी की, जो गरीब की जेब पर बड़ा डाका है। राशन की दालों में व अन्य सामान में भी भारी इजाफा किया गया है। छोटे-छोटे कामो के लिये लगने वाली कोर्ट फीस, स्टॅम्प ड्यूटी में 500 प्रतिशत तक टैक्स लगाया है और रजिस्ट्री फीस को 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है।

डॉ. बिन्दल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आवागमन का एकमात्र साधन एचआरटीसी की बसें है। ढाई वर्षो में एचआरटीसी ने दूर दराज में जाने वाले अनेकों रूट बंद कर दिए और लोगों को टैक्सियां हायर करके बीमारी की अवस्था में शहरों में आने को मजबूर किया।

महिलाओं को मिलने वाली बस किराए की सबसिडी बंद करके बहनो के आवागमन पर रोक लगाई।

घरों में इस्तेमाल होने वाले छोटे-बड़े सामान पर टैक्स लगाकर गांव के गरीब को जोर का झटका दिया और अब सरकार ने लम्बी दूरी की बसों के किराए में बेतहाशा वृद्धि करके प्रदेश की जनता की जेब पर डाका डाला है।

कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी पर करारा प्रहार करते हुए डॉ. बिन्दल ने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी जो 2022 के चुनाव में वोट प्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश की जनता को आसमान से तारे तोड़कर लाने को तैयार थी, उसने प्रदेश की जनता के कपड़े उतारने शुरू कर दिए हैं।

प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर आरोप लगाते हुए डॉ. बिन्दल ने कहा कि टैक्स भी लग रहा है, कर्ज भी लिया जा रहा है परन्तु माली हालत का हवाला देकर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, पीएचसी व दफ्तर बंद किये जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों के डेढ़ लाख पदों को समाप्त किया जो कि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ वादा खिलाफी है और विकास विरोधी मानसिकता का परिचायक है।

कांग्रेस सरकार जनता की जेब पर डाल रही डाका: अनुराग सिंह ठाकुर

शिमला/शैल। पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार द्वारा बस के किराये

में भारी बढ़ौत्तरी को जनविरोधी कदम करार देते हुए इसे जनता की जेब पर सरकार द्वारा डाका डालने वाला फ़ैसला बताया है।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा हिमाचल में कांग्रेस सरकार आये दिन जनता विरोधी फ़ैसले ले रही है। आज हिमाचल में कांग्रेस सरकार की कार्यशैली कुशासन का पर्याय बन चुकी है। हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम किराये के बाद आम किराए में भारी बढ़ौतरी कर कांग्रेस सरकार ने जनता को बड़ा झटका देने का काम किया है। हिमाचल सरकार द्वारा हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी की बसों का 15 फीसदी मनमाना किराया बढ़ाया जाना दिखाता है कि इन्हें जनता की फ़िक्र नहीं है। साधारण बस में मैदानी सड़कों पर अब 1 रुपये 60 पैसे प्रतिकिमी व पहाड़ियों इलाकों की सड़कों पर 2 रुपये 50 पैसे प्रति किमी, डीलक्स बस सेवा में मैदानों में सड़कों में 1 रुपये 95 पैसे व पहाड़ी इलाकों में 3 रुपये 10 पैसे प्रति किमी, एसी/सुपर लक्ज़री बसों मैदान की सड़कों पर 3 रुपये 90 पैसे और पहाड़ी सड़कों पर 5 रुपये 20 पैसे की भारी बढ़ौतरी का निर्णय हिमाचल की जनता के जेब पर डाका डालने जैसा है।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा हिमाचल के इतिहास की ये सबसे निकम्मी सरकार है जिसने प्रदेश के हर वर्ग को सिर्फ़ ठगने और जनता पर महंगाई कि बोझ डालने का काम किया है। कांग्रेस राज में हिमाचल में महंगाई की मार से जनता बेहाल है मगर सरकार अपनी नाकामियों का जश्न मनाने में व्यस्त है। पहले पेट्रोल, डीजल, सीमेंट व अब बस किराए में बढ़ौत्तरी सिर्फ़ हिमाचलवासियों के साथ धोखा है। आम जनता ज़रूरी चीजों के बढ़ते दामों से परेशान है लेकिन इस बढ़ौतरी को रोकने के लिए कांग्रेस सरकार कोई ठोस कदम उठाने में नाकाम रही है। हिमाचल में कांग्रेस ने सरकार बनाने से पहले दस गारन्टियां दी थीं, आज इतना समय बीत गया मगर इनकी एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। कांग्रेस राज में हिमाचल की हालत तो ये हो गई है कि आज मुफ़्त बिजली का वादा करके उस पर सेस, मुफ़्त पानी का वादा करके उस पर चार्ज लगाकर वसूली कर सरकार ने हिमाचल की जनता को छलने का काम किया है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों के समय प्रदेश की जनता से झूठे वादे और झूठी गारंटियां देकर सरकार बनाई थी। हिमाचल की माताएं बहनें अभी भी अपने 1500 रूपये प्रति महीने का इंतजार कर रही हैं। हिमाचल के किसान अभी तक दो रुपये प्रति किलो गोबर और 100 रूपये प्रति लीटर दूध खरीदे जाने का इंतजार कर रहे हैं। हिमाचल के युवा अपनी 5 लाख नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं। हिमाचल के परिवार 300 यूनिट फ्री बिजली का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश का ये इंतज़ार तो ख़त्म नहीं हुआ उल्टा इन्होंने प्रदेश को भारी भरकम कर्ज के बोझ तले दबा दिया है।

किसानों के नाम पर शोर करने वाली कांग्रेस ने बढ़ाया पांच गुना बिजली का बिल:जयराम ठाकुर

शिमला/शैल। शिमला से जारी बयान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन वाली सुक्खू सरकार शुल्क की सरकार हो गई है और प्रदेशवासियों को लगातार किसी न किसी तरह के शुल्क के झटके दे रही है। व्यवस्था परिवर्तन

वाली सुख की सरकार किसानों को भी बिजली के बिल के झटके दे रही है। सरकार किसानों द्वारा सिंचाई के लिए गये बिजली कनेक्शन के बिजली बिल अब पांच से छ: गुना बढ़ाकर वसूल रही है। यह प्रदेश सरकार की गरीब किसानों के साथ ज्यादती है। खेतों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले बिजली के बिल में इस प्रकार की वृद्धि लोगों समझ के परे है। किसानो को बिजली के बिल में इतनी वृद्धि पर भरोसा ही नहीं हो रहा है और लोग बिजली घरों के चक्कर लगा रहे हैं। यह किसानों के साथ अन्याय है। पूरे देश में कांग्रेस किसान के नाम पर शोर डालती है और हिमाचल में किसानों के सिंचाई के बिल को पांच गुना बढ़ा देती है। क्या मुख्यमंत्री सिर्फ़ अपने हवा हवाई वादों में ही किसानों का हितैषी होने का दावा करते हैं? पूरे देश में कांग्रेस किसान के नाम पर झूठ फैलाये और जहां अपनी सरकार है वहां के किसानों से सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली के दाम पांच गुना बढ़ा दे । किसानों के साथ सरकार की यह मनमानी नहीं चलेगी।

जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश भर से मुझे कई किसान परिवारों के फोन आ रहे हैं। सब बिजली के बढ़े हुए बिल को लेकर अपनी बात कर रहे हैं। लोग अपने बिजली के पुराने और नए बिलों को भेजकर बता रहे हैं कि किस तरह से उन्हें पिछले महीने के मुकाबले पांच गुना से ज्यादा का बिल मिला है। उन्होंने कहा कि ऊना के कुछ किसानों द्वारा भेजे गये बिजली बिल को मैंने देखा जिसमें एक मार्च से एक अप्रैल के बीच 605 यूनिट बिजली खर्च हुई थी और उनका बिजली बिल 669 रूपए का था, जिसमें 370 रुपए सरकार द्वारा लगाये गये सेस के भी शामिल थे। उसी किसान द्वारा मई माह में 591 यूनिट बिजली का उपयोग अपने खेतों की सिंचाई के लिये करने पर बिजली का बिल 3445 रुपए का बिल थमाया गया है। जिसमे 356 रुपए सेस के भी शामिल हैं। ऐसा सिर्फ एक किसान के साथ नहीं है। कई किसानों के बिजली बिल इसी प्रकार कई-कई गुना बढ़ कर आये हैं। यह प्रदेश के किसानों के साथ अन्याय है। सरकार व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर लोगों से इस तरह की वसूली नहीं कर सकती है। सरकार किसानों को राहत देने के बजाये उन्हें बिजली के झटके क्यों दे रही है। इस तरह से बिजली के दामों की वृद्धि किसानों की कमर तोड़ देगी, सरकार अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करे और किसानों को राहत प्रदान करे।

जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार एक 'वेलफेयर स्टेट' के रूप में काम ही नहीं करना चाहती है। सरकार जितनी जिम्मेदारी से प्रदेश के लोगों पर टैक्स लाद रही है और शुल्क लगा रही है, काश उसी तरह से लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखती तो बेहतर था। एक दिन सरकार छुट्टे का बहाना बनाकर बसों का मिनिमम किराया पांच रुपए से बढ़ाकर दस रुपए कर देती है तो कभी लंबी दूरी की बसों का 15 फ़ीसदी से ज्यादा किराया बढ़ा देती है। कभी आउटसोर्स को नौकरी से निकाल देती है तो कभी बेरोजगारों की आवाज़ दबाने की कोशिश करती है, कभी कर्मचारियों को मुकद्दमे के जोर पर डराती है। इसके साथ ही प्रदेश के लोगों से हिमकेयर से होने वाले इलाज की सुविधा छीन लेती है। शगुन, सहारा, स्वावलंबन जैसी योजनाएं बंद करती है। प्रदेश सरकार का किसानों के साथ किया जा रहा है यह बर्ताव ग़लत है और सरकार तानाशाही की बजाये मानवीय दृष्टि से विचार करे।

खेलो इंडिया गेम्स-2025 के लिए ट्रॉयल 10 मई को बिलासपुर में

शिमला/शैल। खेलो इंडिया गेम्स-2025 के लिए हिमाचल प्रदेश की कबड्डी महिला व पुरुष तथा सेपकटाकरा की महिला टीमों के लिए परीक्षण ट्रॉयल का आयोजन 10 मई, 2025 को लुहणू स्टेडियम, बिलासपुर में आयोजित किया जा रहा है।

युवा सेवा एवं खेल विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि 19 से 24 मई, 2025 को केंद्रशासित प्रदेश दादरा नगर, हवेली तथा दमन व दीयू में खेलो इंडिया बीच गेम्स-2025 का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश की कबड्डी महिला व पुरुष तथा सेपकटाकरा की महिला टीमों के लिए परीक्षण ट्रॉयल 10 मई को प्रातः 10 बजे से लुहणू स्टेडियम, बिलासपुर में आयोजित किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि इस ट्रॉयल में शामिल होने के इच्छुक खिलाड़ी हिमाचली प्रमाण-पत्र तथा दो पासपोर्ट आकार के फोटो सहित भाग ले सकते हैं। ट्रॉयल के लिए खिलाड़ियों का पंजीकरण प्रातः 9 बजे से आरम्भ होगा और परीक्षण ट्रॉयल में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को टीए व डीए नहीं दिया जाएगा।

सरकारी कार्यालयों को कांगड़ा स्थानांतरित करने के सरकार के निर्णय की सराहना

शिमला/शैल। आयुष, युवा सेवाएं एवं खेल, विधि मंत्री यादविंद्र गोमा और उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने शिमला से सरकारी कार्यालयों को कांगड़ा स्थानांतरित करने के सरकार के निर्णय की सराहना की और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने जिला शिमला स्थित वन विभाग के वन्य जीव विंग को जिला कांगड़ा के धर्मशाला स्थित सीपीडी केएफडब्ल्यू परियोजना कार्यालय भवन में स्थानांतरित करने को स्वीकृति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के मुख्यालय को भी शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने का फैसला लिया है।

उन्होंने कहा कि इन कार्यालयों के स्थानांतरण से प्रदेश की राजधानी में भीड़भाड़ की समस्या के समाधान के साथ-साथ कांगड़ा में समान विकास सुनिश्चित होगा।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लिए गए यह फैसले बताते है कि जिला कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि कांगड़ा के बनखंडी में दुर्गेश अरण्य वन्य प्राणी उद्यान स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में ढगवार में 225 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन से 3 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले अत्याधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की आधारशिला रखी है।

पौंग जलाशय में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वॉटर स्पोर्ट्स गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसमें मोटर बोट, जैट-स्की, क्रूज आदि सुविधाएं शामिल हैं। कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार किया जा रहा है। इन निर्णयों से निकट भविष्य में जिले में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी, स्थानीय युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित होंगे और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी।

उन्होंने कहा कि विगत में राज्य में कांग्रेस के शासनकाल के दौरान जिन महत्वपूर्ण कार्यालयों को ज़िला कांगड़ा में स्थानांतरित किया गया था, उसमें हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड भी शामिल है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी पहली बार कांग्रेस के शासनकाल में आयोजित किया गया था।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

क्या सरकार की साख नयी कार्यकारिणी के गठन में समस्या है?

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ब्लॉक स्तर से लेकर प्रदेश तक की कार्यकारिणीयां पिछले नवम्बर से भंग है। केवल प्रदेश अध्यक्षा ही सारा काम देख रही हैं। कार्यकारिणीयां भंग करने के लिये तर्क दिया गया था कि निष्क्रिय पदाधिकारियों के स्थान पर सक्रिय कार्यकर्ताओं को पदभार दिये जाएंगे। फिर सक्रिय कार्यकर्ताओं का पता लगाने के लिये हाई कमान द्वारा पर्यवेक्षकों की टीम भेजी गयी थी। इस टीम की रिपोर्ट गये हुये भी काफी समय हो गया है। इसी बीच प्रदेश प्रभारी को भी बदल दिया गया। अब प्रदेश अध्यक्षा का भी कार्यकाल पूरा हो गया है और उनके स्थान पर नया अध्यक्ष बनाने की भी चर्चाएं चल पड़ी हैं। यह कहा जा रहा है कि नया अध्यक्ष प्रदेश के जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुये अनुसूचित जाति के किसी विधायक को बनाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह की वस्तुस्थिति प्रदेश सरकार की चल रही है उसको सामने रखते हुये यह नहीं लगता कि संगठन की कार्यकारिणीयां बनाना इतना आसान होगा। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से उपमुख्यमंत्री की सोशल मीडिया पर डाली गयी पोस्ट और उसका लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह द्वारा समर्थन किया जाना सामने आया है उससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार और संगठन में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जो कुछ घटा है उसका यदि संज्ञान किया जाये तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार और संगठन में कोई तालमेल नहीं बैठ पाया है। यह एक स्थापित सत्य है कि कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों में सरकार बनने के बाद संगठन का स्थान दूसरे दर्जे पर आ जाता है क्योंकि संगठन का सरकार पर कोई दबाव नहीं रह जाता है। प्रदेश में कांग्रेस का संगठन इसी नीयत और नीति का शिकार रहा है। क्योंकि सरकार व्यवस्था परिवर्तन के ऐसे अपरिभाषित सूत्र को अपना नीति वाक्य बनाकर चली जिसमें सरकार में भी धीरे-धीरे सारा कुछ मुख्यमंत्री में ही केंद्रित होकर रह गया। इसका परिणाम यह हुआ कि मुख्यमंत्री पर शीर्ष अफसरशाही का एक सीमित सा वर्ग हावी होकर रह गया। परिणामस्वरूप प्रशासन में शीर्ष से लेकर नीचे तक अधिकारी-कर्मचारी अपने-अपने स्थानों पर यथास्थिति बने रहें जिनकी कारगुजारियों से भाजपा चुनाव हारी थी। इससे फील्ड में बैठा हुआ कांग्रेस का कार्यकर्ता और दूसरा समर्थक अपने को पार्टी और सरकार से जोड़ने की बजाये पहले तो तटस्थ रहा और फिर धीरे-धीरे छिटककर किनारे बैठ गया। कार्यकर्ताओं को सरकार में समायोजित करने के सारे प्रयास जब असफल हो गये तो पार्टी के छः विधायकों को संगठन से बाहर जाने पर विवश होना पड़ा। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल पूरी तरह से टूट गया। दूसरी ओर सरकार ऐसे अन्त:विरोधी फैसले लेते चली गयी जिससे सरकार की अपनी साख गिरनी शुरू हो गयी। प्रदेश की कठिन वित्तीय स्थिति पर प्रदेश को श्रीलंका जैसे हालात हो जाने की चेतावनी देते हुये स्वयं अपने खर्चों पर कंट्रोल करना भूल गयी। मुख्यमंत्री अपने मित्रों को सरकार में स्थापित करने में इस हद तक चले गये कि मित्रों की सरकार होने का तमगा ले बैठे। वितीय संकट के कारण आज सभी वर्गो को एक साथ वेतन और पैन्शन नहीं मिल पा रही है। जो गारंटियां चुनाव के दौरान जनता को देकर आये थे उन पर अमल भाषणों में ही है जमीन पर नहीं। राजस्व बढ़ाने के लिये प्रदेश के हर वर्ग पर परोक्ष/अपरोक्ष इतना टैक्स भार लाद दिया है कि आम आदमी परेशान हो उठा है। सरकार से आम आदमी कितना खुश है इसका अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री को अपनी धर्मपत्नी को विधानसभा का उपचुनाव जितवाने के लिये कांगड़ा सहकारी बैंक और जिला समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से 78 लाख कैश चुनाव क्षेत्र में चुनाव आचार संहिता के दौरान बंटवाना पड़ा है। ऐसे में आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में कितने चुनाव क्षेत्रों में ऐसे पैसा बांटा जा सकेगा? जिस कार्यकर्ता के सामने सरकार की इस तरह की कारगुजारी होगी वह क्या कह कर सरकार और संगठन की जनता में वकालत कर पायेगा? इस समय सरकार अपने फैसलों के लिये जरूरत से ज्यादा विवादित हो गयी है। रेरा में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां और उपभोक्ता संरक्षण परिषद की प्रस्तावित नियुक्तियां बहुत अरसे से प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित हो चुकी है लेकिन सरकार ने उन्हें अधिमान नहीं दिया है। एक तरह से न्यायालय की निष्पक्षता पर यह स्थिति अपरोक्ष में प्रश्न चिन्ह लगाने वाली हो जाती है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। कुल मिलाकर सरकार किसी एक मानक पर भी खरी नहीं उतर रही है। यह आशंका बढ़ती जा रही है कि हिमाचल सरकार के फैसले राष्ट्रीय स्तर पर समस्याएं पैदा करेंगे। इस वस्तुस्थिति में संगठन के लिये नया अध्यक्ष और कार्यकारिणी का चयन एक चुनौती बनता जा रहा है?

नादौन में ई-बस डिपो के लिए

पृष्ठ 1 का शेष

हुआ है। जिसमें मुख्य सचिव से लेकर सारा शीर्ष प्रशासन मौजूद था। नादौन में जिस राजस्व अधिकारी ने इस खरीद बेच के दस्तावेज सत्यापित किये हैं क्या उसको यह जानकारी नहीं रही होगी कि विलेज कॉमन लैण्ड की खरीद बेच हो रही है जबकि पर्चा जमाबन्दी में यह उल्लेख है कि ताबे हकूक बर्तनदारान। ऐसे में जब 2,60000 में 2015 में खरीदी गई जमीन को 2024 में एच.आर.टी.सी. को करीब सात करोड़ में बेच दिया गया और इसी पूरी प्रक्रिया में सारा शीर्ष प्रशासन मंत्री परिषद सहित संबंद्ध रहा है तब किसी ने भी इस पर कोई प्रश्न क्यों नहीं उठाया यह सवाल आज हर जुबान पर आ गया है। इस संबंध में सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज पाठकों के सामने रखे जा रहे हैं क्योंकि यदि सरकार इस तरह के सौदों से परहेज करती तो शायद उसे यह किराया बढ़ाने की आवश्यकता ही न पड़ती।

S.No	Khasra No.	Total Area	Area Purchased	Seller	Buyer	Date of Purchase	Value of Purchase
1	1677	02-68-84 Hectare (70 Kanal)	00-03-84 Hectare (1 Kanal)	Maheshwar Singh	Ajay Kumar	21/02/15	₹60,000.00
2	1677	02-68-84 Hectare (70 Kanal)	00-07-68 Hectare (2 Kanal)	Maheshwar Singh	1. Rajender Singh Rana 2. Prabhat Chand	25/03/15	₹80,000.00
3	1677	02-68-84 Hectare (70 Kanal)	02-57-32 Hectare (67 Kanal)	Maheshwar Singh	1. Rajender Singh Rana 2. Prabhat Chand 3. Ajay Kumar	27/03/15	₹1,20,000.00
						Total Purchase Value of 02-68-84 Hectare (70 Kanal)	₹2,60,000.00

-12-

(2037) (25)

Statement may have suffered. Hence this objection cannot stand.

18. In the written objection filed by Shri Maheshwar Chand land owner a number of other points have also been raised but they have not been pressed by the learned counsel for the said landowner in the course of his arguments. Hence I do not think it necessary to discuss these points.

19. From the record it is clear that Shri Maheshwar Chand land owner has in his family no separate unit which could be allotted land. This being the position Shri Maheshwar Chand is entitled to retain for himself an area measuring 30 acres i.e. 316 Kanals 10 Marlas only as permissible area and the remaining area measuring ~~18712~~ 18689 Kanals ~~8~~ 1 Marla deserves to be declared as surplus. An application dated 14.11.1975 has been filed on behalf of Shri Maheshwar Chand land owner in which a prayer is made that the area comprising Khasra No. 513, 276, 268, 269, 255, 246, 247, and Khasra Nos. 516 Min(27-11) situated in Tika Bela and Khasra No. 11 situated in Tika Tillu totalling 316 Kanals 10 Marlas may be allowed to him as permissible area. Under Section 8 of the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act the choice of selection of the permissible area is given to the land owner concerned. In view of this provision the area mentioned by the land owner in his application dated 14.11.1975 i.e. the land comprising Khasra No. 513 measuring 152 Kanals 14 Marlas, Khasra No. 276 measuring 8 Kanals, Khasra No. 268 measuring 2 Kanals 9 Marlas, Khasra No.269

-13-

(2039) (27)

measuring 2 Kanals 5 Marlas, Khasra No. 255 measuring 3 Kanals 16 Marlas, Khasra No.246 measuring 5 Kanals 5 Marlas, Khasra No.247 measuring 1 Kanal 16 Marlas and Khasra No. 516 Min measuring 27 Kanals 11 Marlas situated in Tika Bela and Khasra No. 11 measuring 112 Kanals 14 Marlas situated in Tika Tillu totalling 316 Kanals 10 Marlas is allowed to be retained by the land owner as permissible area and the remining area measuring ~~18712~~ 18689 Kanals ~~8~~ 1 Marla (detailed in Annexure IV to XIX) is hereby declared as surplus area. Now a final statement as required under Sub Section(3) of Section 10 be prepared in terms of this order and then the case be put up on 29-XI-1975 for making necessary orders for the publication of the final statement.

Announced in the presence of the counsel for the parties.

HAMIRPUR
NOVEMBER, 22,
1975.

Kam Singh 22/XI/1975
COLLECTOR
UNDER THE HIMACHAL PRADESH
CEILING ON LAND HOLDINGS ACT: